भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3760

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है)

बढ़ते घरेलू ऋण और उधार लेने की प्रवृत्ति का प्रभाव

3760. श्री गौरव गोगोई:

एडवोकेट अदूर प्रकाश:

श्री बैन्नी बेहनन:

डॉ. नामदेव किरसान:

डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण सहित घरेलू ऋण स्तरों से संबंधित डेटा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों पर बढ़ते ऋण बोझ को कम करने के लिए विनियामक हस्तक्षेपों सहित क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता व्यय पर बढ़ते घरेलू ऋण के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण सहित घरेलू वित्तीय देनदारियों का स्टॉक, मार्च 2024 के अंत तक ₹ 120.96 लाख करोड़ है।

(ख) प्रमुख सुधार उपाय के रूप में, केंद्रीय बजट 2025-26 में यह प्रस्तावित किया गया है कि नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। स्लैब और दरों में बदलाव के साथ, प्रस्तावित आयकर ढांचा से मध्यम वर्ग का कर काफी हद तक कम होने और उनके हाथों में अधिक पैसा बचने की उम्मीद है, जिससे घरेलू बचत को बढ़ावा मिलेगा। व्यवसाय करने में आसानी, कौशल, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और समग्र आर्थिक विकास पर सरकार द्वारा बल दिए जाने से मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों की आय और वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 में प्रकाशित अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि घरेलू ऋण में वृद्धि औसत ऋणभार में वृद्धि के बजाय उधारकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण होती है। 28 फरवरी 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, घरेलू सकल प्रयोज्य आय और निजी अंतिम उपभोग व्यय में वर्ष 2019-20 और वर्ष 2023-24 के बीच संयोजित औसत वृद्धि दर, दोनों वर्तमान कीमतों क्रमशः 10.1 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत पर, एक-दूसरे के लगभग समतुल्य थी।

****